भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 135

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है।)

'वित्तीय समस्याएं'

135. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कोविड-19 वैश्विक महामारी से हुई वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्र-वार पुनर्निर्माण और क्षति-नियंत्रक कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सरकार ने 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवम्बर 2021 को घोषित आत्मानिभर भारत पैकेजों के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 29,87,641 करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की है (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए प्रदान की गई राशि, जुलाई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आरबीआई द्वारा घोषित उपायों सहित)। इसके अलावा, 28.06.2021 को 6.28 लाख करोड़ रुपये के कोविड प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की गई है। आत्मानिर्भर भारत पैकेज और 28.06.2021 को घोषित उपायों का विवरण **अनुबंध** में है।

*****

अनुबंध

19.07.2021 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 135 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. रुपये 3 लाख करोड़ व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा, एमएसएमई सहित
2. रुपये 20,000 करोड़ तनाव एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण
3. रुपये 50,000 करोड़ फंड की एमएसएमई फंड के माध्यम से इक्विटी अर्क
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. सरकार निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदाएं 200 करोड़ रू. तक
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफ अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीनों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए 12% से 10% करने के लिए 3 महीने के लिए कम किया जा करने के लिए
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. रुपये 90,000 करोड़ णडस्कॉमों के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से दिए गए ठेकेदारों को राहत, जिसमें ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालन के लिए देय तिथियां

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता शिशु मुद्र ऋण -। 1500 करोड़ रु रुपये की राहत
20. रुपये 5000 करोड़ स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधा।
21. 70,000 करोड़ रू. पीएमएवाई तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग के लिए बढ़ावा (शहरी)
22. रुपये 6,000 करोड़ रोजगार बनाना सीएएमपीए निधियों का उपयोग के लिए
23. रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. रुपये 2 लाख करोड़ रियायती ऋण 2.5 बढ़ावा करोड़ किसानों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना

ग. 15.05.2020 को घोषणाएँ

25. रुपये 1 लाख करोड़ किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
26. रुपये 10,000 करोड़ माइक्रो खाद्य उद्यम औपचारिक के लिए योजना (यूके)
27. रुपये 20,000 करोड़ के माध्यम से मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना – 15,000 करोड़ रुपये
30. हर्बल संवर्धन को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल- रुपये 500 करोड़
32. 'टॉप' से कुल - 500 करोड़ रुपये (ओपरेशन ग्रीन्स स्कीम टॉप टू टोटल में यदि ऐसे फलों या सब्जियों की कीमतें ट्रिगर मूल्य से कम होती हैं तो अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन और भंडारण पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है)

33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार

iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में स्व रिलायंस को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने वाला भारत
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में सुधारित व्यवहार्यता गैप वित्त योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमजीएनआरईजीएस के आबंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि
48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट-सीओवीआईडी
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि
51. कंपनी अधिनियम की चूक को कम करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)
56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- रु. की ब्याज मुक्त अग्रिम। 10,000, प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाएगा।
57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक ₹12,000 के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण करोड़ पूंजीगत व्यय

- 8 उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 200 करोड़
- ₹ 450 करोड़ प्रत्येक उत्तराखंड, हिमाचल
- शेष राज्यों के लिए of 7,500 करोड़, वित्त आयोग के विचलन के अनुसार

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020-21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना-कोविड-19 वसूली के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।

60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।

61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य 591.46 लाख करोड़ की पेशकश की।

62. 18,000 करोड़ अतिरिक्त अतिरिक्त पीएम आवास योजना के लिए - शहरी

63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता- सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट

64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत

65. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म

66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़

67. ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है । निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

70. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

(ज) 28.06.2021 को की गई घोषणाएं

1. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 करोड़ रुपए के लोन गारंटी योजना
2. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए
3. सुक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआईएस) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
4. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/गाइडों/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता
5. पहले 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा
6. 31 मार्च, 2022 तक आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार
7. डीएपी और पी एंड के उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रु. की अतिरिक्त सब्सिडी
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार-मई से नवंबर, 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न
9. बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/बाल चिकित्सा विस्तरों पर जोर देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रु. से अधिक
10. पोषण, जलवायु लचीलापन और अन्य लक्षणों के लिए जैव-फोर्टिफाइड फसल की 21 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया जाना
11. 77.45 करोड़ रु. के पैकेज के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरूद्धार
12. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रु. प्रोत्साहन
13. निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रु. का प्रोत्साहन
14. भारत नेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्राडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रु.
15. 2025-26 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल बढ़ाना
16. सुधार आधारित परिणाम-लिम्ड विद्युत वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रु.
17. आस्ति मुद्रीकरण और पीपीपी परियोजनाओं के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया।

*****